

संघर्ष से सिद्धि

खबरों के साथ, हर नजरिये की बात

Sangharshesiddhi@gmail.com

उज्जैन शुक्रवार 24 अप्रैल 2026

वर्ष-04 अंक-258

पृष्ठ-08, मूल्य-01 रुपये

“स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र को शक्तिशाली बनाओ”

ईसाई मशीनरी के धर्म परिवर्तन की मुहिम थमने का नाम नहीं ले रही अब ना-ना जतन...

तिलक लगाना छोड़ो और पूजा बंद करो, बाइबल थमाकर बोले, अब तुम ईसाई बन गए

धर्म बदलो, प्रार्थना करो, बीमारी दूर होगी प्रार्थना के बहाने धर्म बदलने का खेल

खरगोन। खरगोन जिले के भीकनगांव क्षेत्र के बमनाला में एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति को एक घर में बुलाकर उसका ब्रेनवॉश कर धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, इसके पास से बाइबल, प्रोजेक्टर, ईसाई धर्म का साहित्य सहित लैपटॉप मिला है।

खरगोन। खरगोन जिले के भीकनगांव थाना क्षेत्र के बमनाला में कथित रूप से धर्मांतरण कराने के प्रयास का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक ग्रामीण की शिकायत के आधार पर चार लोगों के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम बमनाला निवासी बबलू पिता राजेश दागोडे (29 वर्ष) ने शिकायत दर्ज कराई है कि बुधवार दोपहर करीब 12 बजे वह सेल्दा रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास से गुजर रहा था। इसी दौरान उसने राजू बडोले के घर पर काफी भीड़ देखी। जब वह वहां पहुंचा तो उसे घर के अंदर बुलाया गया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, अंदर

मौजूद लोगों ने उसे ईसा मसीह की प्रार्थना करने के लिए कहा और बताया कि ऐसा करने से वह हमेशा स्वस्थ रहेगा तथा उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आरोप है कि उसे अपने पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाज छोड़ने के लिए भी कहा गया। उसे हिंदू देवी-देवताओं की पूजा बंद करने, तिलक न लगाने और अपने धर्म का पालन नहीं करने के लिए कहा गया।

बाइबल देकर कहा, अब तुम ईसाई बन चुके हो!

शिकायत में यह भी उल्लेख है कि कुछ देर बाद उसे बाइबल दी गई और कहा गया कि वह अब ईसाई बन चुका है। साथ ही उसे नए धर्म के फायदे बताए गए और यह भरोसा दिलाया गया कि धर्म बदलने के बाद उसे किसी प्रकार की परेशानी का सामना

नहीं करना पड़ेगा।

पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की

घटना के बाद शिकायतकर्ता ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही भीकनगांव थाना क्षेत्र की बमनाला पुलिस चौकी ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चार लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों में राजू बडोले निवासी बमनाला, बबलू जमरे निवासी ढसलगांव, पंकज बारिया निवासी झाबुआ और सेतु मेडा निवासी झाबुआ शामिल हैं। सभी के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरोपियों से 13 बाइबल लैपटॉप, साउंड बरामद

पुलिस ने उनके पास से तेरह बाइबल, लैपटॉप, साउंड सिस्टम, प्रोजेक्टर और ईसाई साहित्य बरामद किया है। बमनाला चौकी प्रभारी राजेंद्र अवास्या ने बताया कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय



के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

खरगोन जिले में पहले भी धर्मांतरण के मामले सामने आए आदिवासी इलाकों में प्रार्थना सभा के नाम पर बरगला रहे। कैसर

जैसी बीमारियों तक के ठीक होने का दावा करते हैं।

प्रार्थना के नाम पर ग्रामीणों को एकत्र कर धर्मांतरण करने के लिए जबरन दबाव बनाता।

इनका कहना.....

पुलिस मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य संबंधित व्यक्तियों से भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पुलिस साक्ष्य एकत्र करने और मामले की पुष्टि करने में जुटी हुई है

-राजेंद्र अवास्या, चौकी प्रभारी बमनाला

पश्चिम बंगाल में शाम छह बजे तक रिकॉर्ड तोड़ 91.64 प्रतिशत मतदान हुआ

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पहले चरण में शाम छह बजे तक रिकॉर्ड तोड़ 91.64 प्रतिशत मतदान हुआ। राज्य के दक्षिण दिनाजपुर जिले में सबसे अधिक 94.50 प्रतिशत और केलिमपोंग जिले में सबसे कम 82.89 प्रतिशत मतदान हुआ। इसके अलावा अलीपुरद्वार में 90.28, बांकुरा में 91.34, बीरभूम में 93.37, कूचबिहार में 94.12, दार्जिलिंग में 87.91, जलपाईगुड़ी में 92.85, झारग्राम में 91.74, मालदा में 91.90, मुर्शिदाबाद में 92.76, पश्चिम

बर्धमान में 88.96, पश्चिम मेदिनीपुर में 91.69, पूर्वी मेदिनापुर में 90.19, पुरलिया में 89.26 और उत्तर दिनाजपुर में 91.84 प्रतिशत मतदान हुआ। राज्य में इक्का-दुक्का घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। बीरभूम जिले में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता घायल हो गया। दक्षिण दिनाजपुर जिले के कुमारगंज से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर हमले के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया

है। इसके अलावा कहीं से कोई अप्रिय घटना की रिपोर्ट सामने नहीं आयी है। मतदान



शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से पहले चरण में आज 152 सीटों पर मतदान समाप्त

हो गया है। मतदान सुबह सात बजे से शुरू हो गया। मतदान का समय समाप्त होने से पहले मतदान केन्द्रों में पहुंचे मतदाता अभी भी मतदान कर रहे हैं। बंगाल में भीषण गर्मी के बावजूद सभी मतदान केन्द्रों पर सुबह से ही मतदाता लम्बी कतार में लगे हुए देखे गये। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए कुल 44,378 मतदान केन्द्र बनाये गये। जिन सीटों पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, उनमें नंदीग्राम, खड़गपुर, पुरलिया, बांकुड़ा और झारग्राम सीटों शामिल हैं। चुनाव आयोग ने राज्य में

चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किये हैं और संवेदनशील इलाकों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सघन तैनाती की गयी है। आयोग ने राज्य के मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल में वाम समर्थकों को कथित तौर पर वोट डालने से रोकने के मामले में रिपोर्ट मांगी है। राज्य में सिलीगुड़ी और माटीगाड़ा में अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन किया।

कलेक्टर ने झाबुआ बस स्टैंड क्षेत्र में अस्थायी दुकानों एवं अतिक्रमण को हटाने और आवागमन व्यवस्थित करने के लिए निर्देश

संजय जैन सह संपादक

झाबुआ। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि वर्तमान MoRTH (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) की गाइडलाइन के अनुसार फूलमाल तिराहा को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है। इस स्थान पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए रम्बल स्ट्रिप एवं संकेतक लगाने की अनुशंसा की गई है। कलेक्टर ने NHAI को निर्देशित किया कि उक्त सुधारात्मक कार्य 15 दिवस के भीतर पूर्ण किया जाए।

कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म प्लान तैयार कर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सड़क दुर्घटनाओं एवं मृत्यु दर में 50 प्रतिशत की कमी लाई जाए। साथ ही, शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु डिजिटल जंक्शन के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाने के निर्देश दिए।

बैठक में बस स्टैंड झाबुआ क्षेत्र में यातायात सुधार के लिए अस्थायी दुकानों एवं अतिक्रमण को हटाने, आवागमन को व्यवस्थित करने तथा नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई करने हेतु पुलिस एवं सीएमओ को निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त छत्री चौक, गांधी प्रतिमा के पीछे एवं पुराने शिक्षा विभाग के पास अस्थायी पार्किंग विकसित करने के निर्देश दिए गए। छोटे तालाब पर निर्मित वॉकिंग पाथवे को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।

कलेक्टर ने सीएमओ एवं लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि 15 दिवस के भीतर आवश्यक स्थानों पर स्पीड ब्रेकर निर्माण की कार्रवाई पूर्ण की जाए।

बैठक में जानकारी दी गई कि 22 अप्रैल 2026 तक जिले में 372 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 58 लोगों की मृत्यु तथा 449 लोग घायल हुए। इसके अलावा जनवरी से अब तक 7,899 चालानी कार्रवाई की गई है।

कलेक्टर ने हेलमेट की अनिवार्यता को सख्ती से लागू करने एवं रेंडम चेकिंग



बढ़ाने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री कैंसलरी उपचार योजना के अंतर्गत जिले में 26 अस्पताल इम्पैन्लड हैं। हाल ही में प्राप्त 15 आवेदनों में से 13 को स्वीकृति प्रदान की गई है। कलेक्टर ने जिला अस्पताल में इस योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए तथा अस्पताल परिसर के आसपास अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटाने को कहा।

राहवीर योजना के अंतर्गत प्रकरण भेजने से पूर्व सहायता के प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही जिले के सभी बस स्टैंडों पर

यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने एवं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि आगामी बैठक में सभी विभाग अपने-अपने शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म प्लान के साथ पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित हों।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया, संयुक्त कलेक्टर विजय कुमार मंडलोई, जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती कृतिका मोहटा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

पुलिस थाना नीमच केंट एवं सायबर सेल की टीम की क्रिकेट सट्टे के विरुद्ध कार्यवाही

नीमच। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल द्वारा अपराध समीक्षा बैठक के दौरान जिले के समस्त थाना प्रभारियों को सट्टा, जुआ एवं आईपीएल के दौरान लगने वाले क्रिकेट सट्टे पर सख्ती से अंकुश लगाने संबंधी निर्देश दिये गये हैं।

पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया, नगर पुलिस अधीक्षक सुश्री किरण चौहान के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी थाना नीमचकैण्ट निरीक्षक सौरभ शर्मा एवं प्रभारी सायबर सेल प्रधान आरक्षक प्रदीप शिन्दे के नेतृत्व में गठित टीम को दिनांक 22.04.2026 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि मोहम्मद सलीम निवासी मुलचंद मार्ग नीमच का अपने साथी फरीद अंसारी निवासी बघाना के साथ वेन्यू कार नम्बर एमपी 44 सी.बी 2129 में फोन पर अवैध सट्टा लिखकर लाभ कमा रहे हैं। जो मुखबिर सूचना पर कार्यवाही करते हुये आरोपी 01. मोहम्मद सलीम पिता अब्दुल मजीद उम्र 55 साल निवासी बोहरा



कबीराना के पास मुलचंद मार्ग नीमच व 02. फरीद पिता सिराजुद्दीन अंसारी उम्र 42 साल निवासी जुलाहा मोहल्ला बघाना को अपने मोबाईल पर राजस्थान रायल्स व लखनऊ सुपर जाइंट्स के मध्य खेले जा रहे आईपीएल टी-20 मैच में सट्टा करना पाया गया। उक्त आरोपीगणों से पुछताछ करते बताया कि उनके द्वारा उनसे जप्त कार में घुम फिरकर लोगो को क्रिकेट मैच में भाव बताकर सट्टा लिखा जाता है व सट्टा अपने अन्य फरार साथियों को उतार अवैध लाभ कमाया जाता है। जिस पर से थाना नीमचकैण्ट पर उक्त आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 218/2026 धारा 4-क सट्टा अधिनियम का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आनलाईन क्रिकेट सट्टा करते 1 आरोपी को पकड़ा

शाहिद अजमेरी

मंदसौर। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर टी.एस. सिंह बघेल व नगर पुलिस अधीक्षक मंदसौर जितेन्द्र सिंह भास्कर के निर्देशन में तथा थाना प्रभारी निरी. पुष्पेन्द्र सिंह राठौर के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 22-04-26 को 01 आरोपी को क्रिकेट सट्टा करते पकड़ा जिसके कब्जे से 80 हजार रुपये का आनलाईन क्रिकेट हिसाब व हिसाब डायरी जप्त की गई है। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22-04-26 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर

आरोपी भावेश पिता सुजानमल ओस्तवाल उम्र 34 साल निवासी वार्ड 05 कर्मचारी कोलोनी मंदसौर को कालाखेत स्कूल ग्राउंड से आनलाईन क्रिकेट सट्टा करते आरोपी के कब्जे से 80 हजार रुपये का आनलाईन क्रिकेट हिसाब व हिसाब डायरी जप्त की गई है। जिस पर अपराध क्रमांक 272/26 धारा 4 क द्युत विधान का दर्ज किया जाकर अनुसंधान में लिया गया है। इससे पूर्व भी थाना कोतवाली द्वारा आनलाईन आईपीएल क्रिकेट सट्टे में कार्यवाही करते भिन्न-भिन्न 04 प्रकरण दर्ज किये जाकर अनुसंधान में लिये हैं जिसमे आगे भी निरंतर कार्यवाही जारी है।

कांग्रेस नप अध्यक्ष के खिलाफ न्यायालय जाना महंगा पड़ा

रतलाम। जिला कांग्रेस कमेटी रतलाम ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। जिला अध्यक्ष हर्षविजय गेहलोत ने सैलाना नगर परिषद की पार्षद श्रीमती सलोनी मांडोत, पूर्व पार्षद जितेंद्र सिंह राठौर और प्रशांत मांडोत को प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, पार्षद सलोनी मांडोत ने सैलाना नगर परिषद अध्यक्ष के वित्तीय अधिकारों को रोकने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। पार्टी नेतृत्व ने इसे संगठन के खिलाफ एक गंभीर कदम माना। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ये तीनों सदस्य निरंतर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए और इन्होंने संगठनात्मक अनुशासन का उल्लंघन किया है।

संगठन की छवि को धूमिल करने का आरोप

जिला अध्यक्ष हर्षविजय गेहलोत द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पार्टी के नियमों एवं सिद्धांतों के विपरीत कार्य करना,



संगठन की छवि को धूमिल करना और वरिष्ठ नेतृत्व के निर्देशों की अवहेलना करना अत्यंत गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इसी के चलते संगठन के हित और अनुशासन बनाए रखने के लिए यह कठोर निर्णय लिया गया है।

इन पर हुई कार्रवाई

जितेंद्र सिंह राठौर पूर्व पार्षद, न.प. सैलाना, श्रीमती सलोनी मांडोत पार्षद, न.प. सैलाना, प्रशांत मांडोत शामिल है। इस कार्रवाई की प्रतिलिपि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और जिला प्रभारी प्रताप ग्रेवाल को भी सूचना हेतु भेजी गई है। राजनीतिक गलियारों में इस निष्कासन को आगामी स्थानीय समीकरणों और पार्टी के भीतर अनुशासन के संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

डीपीसी द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय करडावद बड़ी का आकस्मिक निरीक्षण

संजय जैन सह संपादक

झाबुआ। कलेक्टर डॉ. योगेश भरसट के निर्देशानुसार जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय करडावद बड़ी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान विद्यालय एवं छात्रावास की व्यवस्थाओं का गहनता से अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

निरीक्षण के दौरान बालिकाओं की उपस्थिति, हॉस्टल की स्वीकृत एवं भरी हुई सीटों की स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही नवीन भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन एंट्री कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई तथा संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में सभी प्रविष्टियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

डीपीसी ने छात्रावास परिसर में साफ-सफाई, स्वच्छता एवं समुचित व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देशित किया



कि छात्राओं को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने हेतु नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए तथा सभी आवश्यक सुविधाएं व्यवस्थित रूप से

संचालित रहें। निरीक्षण के दौरान संबंधित स्टाफ को शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करने एवं व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

मोहन सरकार का ऐतिहासिक निर्णय, किसानों के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण पर अब 4 गुना मुआवजा-सरकार का मानना है कि इससे कई विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाएगा.....



डॉ.मोहन यादव-मुख्यमंत्री

झाबुआ/इंदौर (संजय जैन-सह संपादक)। डॉ. मोहन यादव सरकार ने किसानों के हित में एक ऐसा फैसला लिया है जिसे राज्य के इतिहास में ऐतिहासिक माना जा रहा है। सीएम की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों और किसान संगठनों की मांग पर यह बड़ा फैसला लिया गया है।

कृषि भूमि के अर्जन पर बाजार दर से 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इससे न केवल नए जमीन खरीदने में आसानी होगी, बल्कि



भूमि अधिग्रहण -4 गुना मुआवजा

किसानों के साथ-साथ बड़े किसानों से भी गेहूं खरीदा जा रहा है। इसके साथ ही



किसानों को बोनस देने की योजना भी जारी है। मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना की

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम- 2015 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मल्टीप्लीकेशन



फैक्टर 1.0 से बढ़ाकर 2.0 कर दिया गया है। इससे किसानों को बाजार मूल्य का अधिकतम 4 गुना मुआवजा मिलेगा, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। इस निर्णय से सिंचाई परियोजनाएं, सड़कें, पुल, रेलवे और बांध निर्माण जैसे विकास कार्यों में तेजी आएगी। किसान परिवारों को अधिक राशि मिलने से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति बढ़ेगी।

बढ़ रही मेट्रोपोलिटन सिटी की आवश्यकता.....

प्रदेश में मेट्रोपोलिटन सिटी की आवश्यकता बढ़ रही है। पिछले तीन वर्षों में 55 हजार से अधिक किसानों को विभिन्न परियोजनाओं के तहत 16 हजार करोड़ मुआवजा वितरित किया गया है। यदि



वार्षिक आधार पर देखें, तो मुआवजा 5000 करोड़ रूपए से चार गुना बढ़कर अब 20 हजार करोड़ रूपए होगा। यह किसानों के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है।

गेहूं उपार्जन की स्थिति.....

वैश्विक परिदृश्य में गेहूं का निर्यात कम है, लेकिन सरकार किसानों के लिए खड़ी है। छोटे और मझौले किसानों को प्राथमिकता देते हुए गेहूं की खरीद जारी है। पिछले वर्ष का गेहूं वेयरहाउस में स्टॉक है और इस वर्ष उत्पादन भी बढ़ा है। राज्य सरकार सुनिश्चित कर रही है कि वो

किसानों के हित में गेहूं की पूरी खरीद कर सके।

लाड़ली बहनों के लिए राहत.....

लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाकर महिला सशक्तिकरण को और मजबूती दी गयी है। सरकार ने सभी योजनाओं को जारी रखा है और कोई भी योजना बंद नहीं की है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4 लाख 21 हजार करोड़ रूपए का बजट पेश किया गया है, जो कि सभी प्रकार के वित्तीय प्रबंधन में सरकार की नीति को दर्शाता है।



भूमि अधिग्रहण कार्यों में भी तेजी आएगी। इस निर्णय से सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। सीएम ने हाल ही में किसानों के हित में कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कृषक कल्याण वर्ष-2026 में निरंतर कार्य करेगी। छोट, मझौले

राशि बढ़ाने की बात भी कही, जिससे महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास जारी है। इस सबका उद्देश्य किसानों की समृद्धि को बढ़ावा देना है।

नई संभावना के द्वार.....

मध्यप्रदेश भू-अर्जन पुनर्वासन और

बंद चेकपोस्ट दोबारा शुरू करने हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार का मंथन, विरोध-ट्रांसपोर्टर्स बोले-बढ़ेगा भ्रष्टाचार....



झाबुआ/इंदौर (संजय जैन-सह संपादक)। प्रदेश में बंद चेकपोस्ट दोबारा शुरू करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद ट्रांसपोर्ट कारोबारियों में नाराजगी बढ़ गई

है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इसे भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला फैसला बताते हुए सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। वहीं, सरकार भी कोर्ट के आदेश पर मंथन कर रही है।

विरोध-ट्रांसपोर्टर्स बोले-बढ़ेगा भ्रष्टाचार.....

प्रदेश में बंद पड़े परिवहन चेकपोस्टों को दोबारा शुरू करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार और ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के बीच हलचल तेज हो गई है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि इस आदेश से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। एक तरफ राज्य सरकार इस फैसले के कानूनी पहलुओं का परीक्षण कर रही है, वहीं ट्रांसपोर्ट संगठनों ने आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बेंच में याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के निर्देश पर 30 जून 2024 से प्रदेश के अंतरराज्यीय परिवहन चेकपोस्ट बंद कर



दिए गए थे। यह फैसला चेकपोस्टों पर अवैध वसूली और भ्रष्टाचार की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद लिया गया था। हालांकि अब जबलपुर हाईकोर्ट ने एक

अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर सभी बंद चेकपोस्ट फिर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

सम्पादकीय

उत्तर प्रदेश बोर्ड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपीएमएसपी) ने गुरुवार को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए। एक बार फिर बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी।

हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) की परीक्षा में सीतापुर की कशिश वर्मा और बाराबंकी की अंशिका वर्मा ने 97.83 प्रतिशत अंक हासिल कर संयुक्त रूप से प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं, इंटरमीडिएट (कक्षा 12वीं) में सीतापुर

की शिखा वर्मा ने 97.60 प्रतिशत अंकों के साथ टॉप किया है।

बोर्ड परीक्षाएं प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्थापित 8,033 केंद्रों पर 18

फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित की गई थीं। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से 4 अप्रैल तक कुल 254 केंद्रों पर कराया गया, जिसमें करीब 55,976 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई।

इंटरमीडिएट की लगभग 1.23 करोड़ कॉपियों का मूल्यांकन किया गया। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने बताया कि परिणाम जारी होने के साथ ही टॉपर्स

की सूची भी घोषित कर दी गई है। राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया

जाएगा। छात्र अपने परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, डिजिलॉकर, और एसएमएस के माध्यम से देख सकते हैं। इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच प्रदेश के 8033 परीक्षा केंद्रों पर 15 कार्य दिवसों में शांतिपूर्ण एवं नकलविहीन वातावरण में संपन्न कराई गईं।

हाईस्कूल में लगभग 26.02 लाख और इंटरमीडिएट में 24.91 लाख

परीक्षार्थी शामिल हुए, जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के व्यापक दायरे को दर्शाता है।

परीक्षाओं के सफल आयोजन के बाद 254 मूल्यांकन केंद्रों पर लगभग 2.75 करोड़ उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन 18 मार्च से 4 अप्रैल के बीच मात्र 15 कार्य दिवसों में पूरा किया गया। इस बार परिणाम को त्रुटिहीन बनाने के लिए प्रधानाचार्यों और वरिष्ठ प्रवक्ताओं को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, ताकि मूल्यांकन प्रक्रिया की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।

दो अलग-अलग प्रकरणों में अपहृत बालिकाओं को सकुशल दस्तयाब कर किया परिजनों के सुपुर्द

शाहिद अजमेरी

मंदसौर। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाये जा रहे मुस्कान अभियान अंतर्गत पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के निर्देशन में एवं श्रीमती हेमलता कुरील अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (गरोठ) एवं दिनेश प्रजापति एसडीओपी सीतामऊ के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी शामगढ उप निरीक्षक कपिल सौराष्ट्रीय की टीम द्वारा दो अलग अलग प्रकरणों में अपहृता को दस्तयाब कर आरोपी को किया गिरफ्तार।

दिनांक 05.03.2026 को फरियादी द्वारा अपनी नाबालिक बहन के अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर अपहरण कर ले जाने के संबंध में थाना शामगढ पर रिपोर्ट किया गया जो रिपोर्ट पर से थाना शामगढ पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी जानकारी सायबर सेल मंदसौर से प्राप्त की गई तथा बालिका के निवास के पड़ोसियों से घटना के संबंध में पूछताछ की गई। बालिका के पूर्व में आने जाने वाले परिचितों से भी जानकारी प्राप्त की जाकर साक्ष्य संकलित किए गए एवं प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस टीमे आगर, उज्जैन, इंदौर, खंडवा की ओर लगातार खाना की जाकर बालिका का पता लगाने के प्रयास किए गए साइबर सेल मंदसौर द्वारा प्रदाय तकनीकी साक्ष्य के आधार पर उपनिरीक्षक रवींद्र सिंह दांगी के नेतृत्व की टीम के द्वारा

दिनांक 22-04-26 को नाबालिक अपहृत बालिका को ओंकारेश्वर खंडवा से आरोपी दरबार सिंह निवासी ग्राम कुबडियाखेडी के



कब्जै से सकुशल दस्तयाब कर आरोपी दरबार सिंह को गिरफ्तार किया गया। उक्त अपराध में बालिका के कथनों के आधार पर पाक्सो एक्ट की एवं बलात्कार से संबंधित सुसंगत धाराओं को बढ़ाया गया है तथा आरोपी दरबार सिंह को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, अपहर्ता बालिका के अपहरण में सहयोग करने वाले नरेंद्र सिंह पिता बगदू सिंह को भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया। 02. दिनांक 19.04.2026 को फरियादी ने अपनी नाबालिक लड़की जो दिनांक 18.04.2026 व दिनांक 19.04.2026 की मध्यरात्री मे घर से बिना बताये कही चली जाने व काफी तलाश करने पर कोई जानकारी नहीं मिलने के संबंध मे रिपोर्ट करने पर थाना शामगढ पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 136/2026

धारा 137(2) BNS का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण मे थाना प्रभारी अनिल कपिल सौराष्ट्रीय के नेतृत्व में चौकी चंदवासा व थाना शामगढ पर अपहर्ता की दस्तयाबी हेतु टीम गठित की गई थी, जो गठित टीम के द्वारा अपहृत नाबालिक बालिका की दस्तयाबी हेतु अथक प्रयास किये गये। जिसके चलते आज दिनांक 21.04.2026 को मात्र 48 घण्टे के भीतर नाबालिक बालिका को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है तथा धारा 137(2) बीएनएस अंतर्गत आरोपी दरबारसिंह निवासी लक्ष्मीपुरा को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपी

01. दरबार सिंह पिता प्रहलाद सिंह जाति सोंधिया राजपुत उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम कुबडियाखेडा थाना कोतवाली जिला आगर (म.प्र.)

02 दरबारसिंह पिता अंदरसिंह जाति औढ उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा थाना पीडावा जिला झालावाड राजस्थान

फरार आरोपी

नरेन्द्र सिंह पिता बगदू सिंह सोंधिया राजपूत निवासी लसुडिया गोयल थाना झारडा जिला उज्जैन।

सराहनीय कार्य

उक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक कपिल सौराष्ट्रीय थाना प्रभारी शामगढ, अनिल मनोज महाजन, अनिल रविन्द्र प्रताप डांगी का प्रभार आशीष बेरागी का प्रभार मुजफ्फरउद्दीन, आर मनीष बघेल (सायबर सैल) आर इरफान खान, आर मोकम सिंह।

पानसेमल के मेंद्राणा में चोरों ने लगभग 30 से 32 तोला सोना एवं 10 हजार रु. नगदी पर किया हाथ साफ

पानसेमल। पानसेमल थाना अंतर्गत मेंद्राणा में अंबालाल चौधरी के घर पर रात्रि में लगभग 30 से 32 तोला सोना एवं 10000 रुपए नगदी पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ किया है। अंबालाल चौधरी ने बताया कि हम रात को बरामदे में सो रहे थे। जब सुबह उठे तो हमने पूर्व दिशा के दरवाजे को देखा तो चोरों द्वारा ताला तोड़ा हुआ मिला। हम घबराकर अंदर पहुंचे तो देखा की अलमारी का लॉक टूटा हुआ था सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया है।

जब हमने अलमारी चेक की तो उसमें बैग में रखा 30 से 32 तोला सोना एवं 10000 नगदी गायब है। पश्चात पुलिस को सूचना देने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका पंचनामा बनाया गया है। खरगोन से फिंगरप्रिंट टीम और डॉग स्कॉट टीम घटनास्थल पर बुलाई गई।

जहां उन्होंने सघन जांच शुरू की। थाना पानसेमल के उप निरीक्षक एस के रघुवंशी ने बताया कि घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया है। घर मालिक के मुताबिक घर से सोना और 10000 नगदी चोरी होना बताया गया है।



एक्सपर्ट टीम के द्वारा सघन जांच की जा रही है। वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से चोरों का पता लगाया जाएगा। शीघ्र ही चोरों की तलाश की जाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

घर मालिक अंबालाल चौधरी के पुत्र प्रशांत चौधरी ने कहा कि घर में बड़ी चोरी हुई है। हमें बहुत नुकसान हुआ है। हमारी जिंदगी भर की जमा पूंजी चोरी हो गई है। मेरे माता-पिता बहुत परेशान है। हर संभव प्रयास कर चोरों को पड़कर हमारी जमा पूंजी वापस दिलाने में सहयोग करें।

पालसोड़ा के समीप कार दुर्घटना में तीन लोग घायल जिसमें दो सेन समाज व एक नागदा समाज का शामिल

नीमच। गुरुवार दोपहर में पालसोड़ा-मालथा रोड पर भयंकर सड़क दुर्घटना हो गई जिसमें दो सेन समाज के युवक विशाल-लोकेश सेन एवं मनीष नागदाशामिल हैं। मिली जानकारी अनुसार दुर्घटना में तीनो घायल हो गए थे तीनो को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पालसोड़ा से नीमच जिला अस्पताल लाया गया है। जहां उपचार के दौरान लोकेश पिता नंदकिशोर उर्फ बंटू निवासी अडमालिया का

उनका उपचार किया जा रहा है। तीनों संभवतः एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इधर घटना की जानकारी मिलने



मृत्यु हो गई जबकि विशाल पिता विनोद सैन बिसलवास सोनीगरा, मनीष नागदा अडमालिया के निवासी बताए जा रहे हैं।

पर बड़ी संख्या में सेन समाज और नागदा समाज के लोग जिला चिकित्सालय में पहुंच चुके थे।

जनगणना 2027-तृतीय बैच का प्रशिक्षण प्रारंभ

संजय जैन सह संपादक

झाबुआ। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशानुसार जिले में जनगणना 2027 के सफल, सुव्यवस्थित एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में पर्यवेक्षकों एवं प्रणालियों के तृतीय बैच का प्रशिक्षण 23 अप्रैल से 25 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया जा रहा

है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को जनगणना की प्रक्रिया, डेटा संकलन की विधि, ऑनलाइन प्रविष्टि, प्रपत्रों के सही उपयोग एवं शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही मैदानी कार्य के दौरान आने वाली संभावित समस्याओं एवं उनके समाधान पर भी विशेष मार्गदर्शन दिया जा रहा है, ताकि जनगणना कार्य पूर्ण पारदर्शिता, सटीकता

एवं समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके।



महिला आरक्षण के नाम पर झूठ परोस रही है भाजपा-जिला कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी

धार। धार सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर द्वारा गुरुवार को धार में आयोजित प्रेस वार्ता में महिला आरक्षण को लेकर भ्रामक स्थिति प्रस्तुत की गई है कायदे से सबसे पहले सावित्री ठाकुर जी को प्रेस वार्ता मणिपुर में हो रहे।

आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार पर लेनी चाहिए इस पर उन्हें एक शब्द भी नहीं बोला धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि महिला आरक्षण के नाम पर भाजपा झूठ परोस रही है पूरे देश की जनता समझ रही है कि भाजपा षड्यंत्र कर रही है महिला

आरक्षण के नाम पर परिसीमन का खेल खेल रही है भाजपा।

यह बेहद चिंताजनक है कि जिस महिला आरक्षण विधेयक को वर्ष 2023 में दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित किया गया था, उसी विषय पर आज जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका स्पष्ट मत है कि महिलाओं को अधिकार और भागीदारी देना हमारी मूल विचारधारा का हिस्सा रहा है। पहली बार भी महिलाओं को पंचायत में आरक्षण लाकर कांग्रेस ने अधिकार दिया। कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर सम्मानपूर्वक स्थान

दिया है चाहे वह प्रधानमंत्री पद हो, राष्ट्रपति पद हो, लोकसभा अध्यक्ष का पद



हो या अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां।

यह भी पहली बार देखने में आया है कि 2023 में पारित महिला आरक्षण

विधेयक का वास्तविक क्रियान्वयन 2028 के बाद करने की बात कही जा रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं।

यदि सरकार की नीयत साफ होती, तो वर्तमान लोकसभा की सीटों पर ही महिला आरक्षण लागू किया जा सकता था।

कांग्रेस की मांग स्पष्ट है कि-

● वर्तमान लोकसभा में ही 543 सीटों पर महिला आरक्षण लागू किया जाए।

● देश में शीघ्र जनगणना कराई जाए।

● ओबीसी, एसटी, एससी वर्गों की वास्तविक संख्या स्पष्ट की जाए।

● जिसकी जितनी संख्या, उसकी उतनी भागीदारी के सिद्धांत को लागू किया जाए।

इसके विपरीत, यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर डिजिटल मिशन (सीमांकन) लागू करना चाहती है, वह भी बिना वर्तमान जनसंख्या के सही आंकड़ों के इससे विशेष रूप से भारत के विभिन्न राज्यों के साथ अन्याय होने की संभावना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुनः स्पष्ट करती है कि वह महिलाओं, ओबीसी, एसटी, एससी सहित सभी वर्गों को पूर्ण अधिकार और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

जल गंगा संवर्धन अभियान में जनभागीदारी बढ़ाने में स्वैच्छिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका- वैशाली जैन, अपर कलेक्टर (विकास) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रतलाम

(उपेंद्र पाटोदिया ब्यूरो)

9926809786

रतलाम। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, जिला रतलाम द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के सशक्तिकरण हेतु 'पंच' कार्यक्रम के अंतर्गत जिला पंचायत परिसर में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य जिले में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं की डायरेक्टरी तैयार कर उनके कार्यों को विस्तार देना एवं क्रियान्वयन को सुदृढ़ बनाना रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ अपर कलेक्टर (विकास) एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी वैशाली जैन द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने परिसर स्थित बरगद के पेड़ पर जीवदया हेतु सकोरों

लगाकर पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था करने का संदेश दिया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए वैशाली जैन ने स्वैच्छिक संगठनों से जल गंगा संवर्धन अभियान, जनगणना, ज्ञानोदय अभियान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सर्वांगिक एवं बेस्ट कैंसर जागरूकता, वृहद पौधारोपण एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। जल गंगा संवर्धन अभियान में जनभागीदारी बढ़ाने में स्वैच्छिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, रूप वाटर हार्वेस्टिंग एवं पारंपरिक जल स्रोतों जैसे बावड़ियों के संरक्षण एवं स्वच्छता पर भी विशेष जोर दिया। म.प्र.जन अभियान परिषद की गतिविधियों की समीक्षा की गई तथा

पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, नशामुक्ति अभियान, सृजन, लोककला, रोजगार एवं पर्यावरण से



संबंधित स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त कर शासन की योजनाओं में भागीदारी, क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा,

समाधान और सुधार पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय ने बताया कि जिले में कार्यरत सभी स्वयंसेवी संगठनों की एक समग्र डायरेक्टरी तैयार की जा रही है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं का सूचीकरण किया जाएगा। इस दौरान परिषद की योजनाओं की विस्तृत जानकारी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत की गई।

बैठक में उपस्थित विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने कार्यों का परिचय दिया तथा विभागीय अधिकारियों ने शासन की प्रमुख योजनाओं की जानकारी साझा की।

इस अवसर पर जिला योजना अधिकारी बालकृष्ण पाटीदार ने स्व-गणना

प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा विभागीय अधिकारी उपसंचालक कृषि आर.के. सिंह, उपसंचालक महिला एवं बाल विकास विभाग भारती डांगी, स्वास्थ्य विभाग से डॉ. वर्षा कुरील, डॉ. शीरीन खान, वन विभाग से एस.आर. नगेश, शिक्षा विभाग से जितेंद्र जोशी के द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान की गयी। बैठक में परिषद के विकासखंड समन्वयक शैलेन्द्र सिंह सोलंकी, शिवशंकर शर्मा, निर्मल अमलियार, युवराज सिंह पंवार, रतनलाल चरपोटा, लेखापाल महावीर दास बैरागी, विजयेश राठौड़ सहित अनेक समाजसेवी एवं नवांकुर संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन परिषद के जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय के द्वारा किया गया।

जिला प्रेस क्लब के पदाधिकारियों द्वारा कलेक्टर से भेंट कर किया सम्मान

आशीष वाणी

आलीराजपुर। आलीराजपुर जिला प्रेस क्लब के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर से भेंट कर उन्हें सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि संग्रहण में जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान दिलाने पर सम्मानित किया।

ज्ञातव्य है कि आलीराजपुर जिला ने सशस्त्र सेना झंडा निधि संग्रहण में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए निर्धारित लक्ष्य 3,52,100 रुपये के विरुद्ध 9,53,100 रुपये से अधिक राशि एकत्रित की। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते जिले ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

इस उपलब्धि के लिए महामहिम राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल द्वारा हाल ही में लोक भवन भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर को प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित

किया गया।

इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय पत्रकार संघ यतेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व जिला



अध्यक्ष प्रेस क्लब राकेश तंवर, अध्यक्ष आशीष वाघेला, महासचिव मनीष अरोड़ा और चिराग माहेश्वरी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

जिला पंचायत आलीराजपुर में स्व-गणना हेतु प्रशिक्षण आयोजित

आशीष वाणी

आलीराजपुर। जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण के अंतर्गत स्व-गणना के प्रशिक्षण का आयोजन आज जिला पंचायत सभा कक्ष, आलीराजपुर में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत सीईओ श्रीमती संघमित्रा गौतम ने की। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जनगणना कार्य को

सुचारु, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना है। कार्यक्रम में कार्यालयीन अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। उन्हें जनगणना कार्य निदेशालय, मध्यप्रदेश से नियुक्त जिला प्रभारी श्री सिद्धार्थ गोयल द्वारा जन गणना पोर्टल पर स्व-गणना की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया तथा स्व-गणना के महत्व एवं इसकी प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही

उन्होंने स्वयं भी स्व गणना पोर्टल के माध्यम से स्वयं की गणना की।



13 वर्ष की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी को 7 वर्ष का कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया

जिला ब्यूरो चीफ रेखा लहासे बुरहानपुर। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित महत्वपूर्ण प्रकरण में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट जिला बुरहानपुर द्वारा आरोपी आनंद भिलावेकर को धारा 4(2) सहपठित धारा 18 पॉक्सोम एक्ट में 07 वर्ष का कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे

ने बताया कि दिनांक 18.04.2025 को दोपहर करीबन 02.00 बजे पीडिता बकरिया चराने जंगल गई थी, उसके गांव का आनंद पिता अर्जुन आया और उसके दोनों हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया और दुष्कर्म करने के लिये उसके कपड़े उतार दिये और स्वयं भी अपने कपड़े उतार रहा था पीडिता ने अपने हाथों से मिट्टी उठाई और अभियुक्त आनंद की आंखों में फेककर वहां से भागकर अपने घर आयी और उक्त घटना अपने माता-पिता को बताई और माता-पिता को साथ लेकर खकनार थाने पर रिपोर्ट लेख कराई। पुलिस खकनार द्वारा धारा 64(1),

65(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा ड(2) पॉक्सो एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे द्वारा की गई जिसके पश्चात मान. न्यायालय द्वारा आरोपी आनंद भिलावेकर को धारा 4(2) सहपठित धारा 18 पॉक्सो एक्ट में 07 वर्ष का कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

क्या इस तरीके का घटिया निर्माण करने वाले ठेकेदार होंगे ब्लैक लिस्ट और क्या प्रशासन वसूलेगा इनसे पैसा... ?

महेश्वर तहसील में सीसी रोड और पुलिया निर्माण पर सवाल-क्या थमेगा भ्रष्टाचार?

किशन लाल जागिड़ खरगोन ब्यूरो
संघर्ष से सिद्धि
मो 9829276941

महेश्वर। तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बंडेरा में जो पुलिया निर्माण किया ओर कुछ ही महीनों में उखड़ तो नजर आ रही है और पुलिया निर्माण कार्यों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मौके पर लगे बोर्ड से स्पष्ट है कि क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इन कार्यों की गुणवत्ता पर संदेह जताया जा रहा है

निर्माण में अनियमितताओं की चर्चा
सूत्रों का कहना है कि निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों का पालन पूरी तरह नहीं किया जा रहा। सामग्री की गुणवत्ता और कार्य की तकनीकी प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिससे निर्माण की मजबूती पर शंका बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार निर्माण स्थल पर निगरानी व्यवस्था कमजोर दिखाई दे रही है। संबंधित अधिकारी और तकनीकी अमले की नियमित जांच को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिससे कार्य की पारदर्शिता पर असर पड़ रहा है।

मिलीभगत की आशंका
सूत्रों के हवाले से यह भी चर्चा है कि ठेकेदार और स्थानीय स्तर पर जुड़े जिम्मेदारों



के बीच समन्वय के चलते काम मनमर्जी से किया जा रहा है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मामले ने गंभीर रूप ले लिया है।

सबसे बड़ा सवाल क्या होगी कार्रवाई.. ?
क्या निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच होगी..? क्या गुणवत्ता की तकनीकी जांच कराई जाएगी..?

क्या दोषियों की जिम्मेदारी तय होगी.. ?
लाखों रुपये की लागत से किए जा रहे निर्माण कार्यों में यदि अनियमितताएं सामने आती हैं, तो यह सीधे-सीधे सरकारी धन के उपयोग पर सवाल खड़ा करता है। ऐसे में आवश्यक है कि संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच कर पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करे।

इंदौर एक साल से बंद संभाग की 180 बसें फिर शुरू, शादी-ब्याह के नाम पर चल रही थी यात्रियों से भरी बसें परिवहन विभाग ने अस्थायी परमिटों को परमिट की अनुमति दी



राजेश पिल्लै
इंदौर। इंदौर संभाग के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। संभाग के सभी जिलों से संचालित होने वाली 180 बसें, जो पिछले करीब 1 साल से बंद थीं, वह फिर शुरू होने जा रही हैं। परिवहन विभाग द्वारा अस्थायी परमिटों पर रोक के बाद बंद हुई ये बसें अब स्थायी परमिट पर दौड़ेंगी। इससे यात्रियों के साथ ही बस संचालकों को भी फायदा होगा। उल्लेखनीय है कि करीब 1 साल पहले परिवहन विभाग द्वारा कोर्ट के निर्देश पर अस्थायी परमिटों पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण इंदौर की 400 से ज्यादा बसें बंद हो गई थीं। इन बसों को कुछ बस

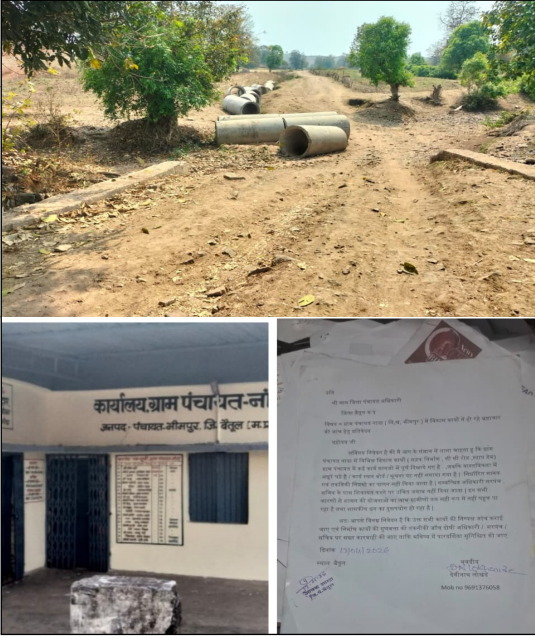
संचालक बरात परमिट लेकर चला रहे थे, लेकिन अक्सर इन्हें भी कार्रवाई के डर से बंद किया जा रहा था। आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि हाल ही में परिवहन विभाग ने स्थायी परमिटों की सुनवाई आयोजित करते हुए 180 बसों को स्थायी परमिट जारी किए हैं। ये वही बसें हैं, जो पहले अस्थायी परमिटों पर चल रही थीं। स्थायी परमिट मिलने पर अब इन बसों का संचालन बेरोकटोक हो सकेगा और यात्रियों को भी बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
रुकेगी अवैध वसूली, नियमित होगा संचालन
अस्थायी परमिटों पर रोक के बाद ज्यादातर बसों के बंद हो जाने का पहले तो

विरोध हुआ, लेकिन सुनवाई ना होने पर बस संचालकों ने बरात और पिकनिक परमिट लेकर बसों का संचालन शुरू कर दिया था। इन बसों में यात्रियों से मनमानी वसूली की जा रही थी और नियमों का पालन भी नहीं हो रहा था। ज्यादातर बसें भी बस स्टैंड के बाहर से चलती थीं, लेकिन अब स्थायी परमिट होने से बसों में यात्रियों से तय किराया लिया जाएगा। बसें भी बस स्टैंड से चलेंगी और यहीं उनके टिकट भी मिलेंगे। बसों को परमिट शर्तों के तहत सभी परिवहन नियमों का पालन भी करना पड़ेगा, अन्यथा परिवहन विभाग कार्रवाई के साथ परमिट निरस्त भी कर सकेगा।

नादा पंचायत में लाखों के निर्माण कार्य कागजों में कैद, धरातल से गायब

ब्यूरो देवीनाथ लोखंडे
बैतूल। जिले की पंचायत व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। विकासखंड भीमपुर की ग्राम पंचायत नादा में लाखों रुपये के शासकीय निर्माण कार्यों के धरातल पर नजर नहीं आने और केवल कागजों में दर्ज होने का गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और संबंधित अधिकारियों पर खुला भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। सूत्रों के अनुसार, पंचायत में सीसी रोड, स्टॉप डेम सहित कई निर्माण कार्य कागजों में

अधिकारी को लिखित शिकायत भी दी गई थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस जांच या कार्रवाई सामने नहीं आई है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी और



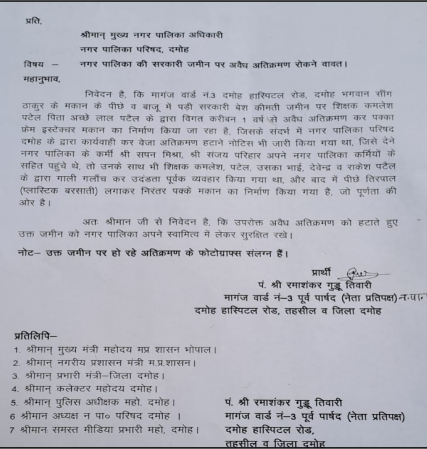
पूर्ण दर्शाए गए हैं, जबकि हकीकत में ये कार्य या तो अधूरे हैं या पूरी तरह से गायब बताए जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता देवीनाथ लोखंडे ने खुलकर विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत में विकास के नाम पर बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं, जिससे ग्रामीणों के अधिकारों और सुविधाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के कृत्य से शासन की योजनाएं बदनाम हो रही हैं और जनता का विश्वास कमजोर पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन

बढ़ गई है, वहीं आरोपियों के हासले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों के बीच अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों में जिम्मेदारों को संरक्षण मिल रहा है या फिर कार्रवाई में अनावश्यक देरी हो रही है। जिले के कलेक्टर डॉ. सौरभ सोनवणे से ग्रामीणों और शिकायतकर्ताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है, तो न केवल पंचायत स्तर पर पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि आम जनता का प्रशासन पर विश्वास भी मजबूत होगा। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है और क्या वास्तव में नादा पंचायत के कथित भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई हो पाती है या नहीं।

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप, कार्रवाई की मांग

जमना प्रसाद चौबे
दमोह। शहर के मांगज वार्ड क्रमांक 3 स्थित हॉस्पिटल रोड क्षेत्र में नगर पालिका की सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया है। पूर्व पार्षद (नेता प्रतिपक्ष) पं. रमाशंकर गुड्डु तिवारी ने इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शिकायत सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

उनके साथ अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज की गई। इसके बाद भी कथित तौर पर निर्माण कार्य जारी रखा गया और अब



शिकायत के अनुसार, भगवान सिंह ठाकुर के मकान के पीछे व बगल में स्थित बेशकीमती सरकारी जमीन पर शिक्षक कमलेश पटेल द्वारा पिछले लगभग एक वर्ष से अवैध कब्जा कर पक्का मकान बनाया जा रहा है। बताया गया है कि इस मामले में नगर पालिका परिषद द्वारा पूर्व में नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। आरोप है कि जब नगर पालिका के कर्मचारी सपन मिश्रा और संजय परिहार अन्य कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे, तो संबंधित व्यक्ति और उसके परिजनों द्वारा

मकान लगभग पूर्णता की ओर है। पूर्व पार्षद ने मांग की है कि उक्त अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाकर जमीन को नगर पालिका के कब्जे में लेकर सुरक्षित किया जाए। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, प्रभारी मंत्री, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, नगर पालिका अध्यक्ष सहित अन्य अधिकारियों को भी प्रतिलिपि भेजी है।

दिपेश पड़ियार

पेटलावद। क्षेत्र के प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र पेटलावद सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार, अस्पताल में पदस्थ कई चिकित्सक अपने निर्धारित ड्यूटी समय के दौरान भी अस्पताल से अनुपस्थित रहते हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि सुबह से ही इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीज घंटों इंतजार करते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं। कई बार तो मरीजों को बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ता है या फिर निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जिससे

पेटलावद सिविल अस्पताल में लापरवाही

ड्यूटी समय में भी नदारद रहते हैं कई चिकित्सक

कलेक्टर साहब एक नजर इधर भी आमजन को है आपसे उम्मीद

उनका आर्थिक बोझ बढ़ता है।

मरीजों और उनके परिजनों ने बताया कि इमरजेंसी सेवाओं में भी लापरवाही देखने को मिलती है और कई बार तो इसी वजह से विवाद भी हुए हैं। जिम्मेदार अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं हैं वो तो अपनी हाल में मस्त हैं शायद यही कारण है कि उनके द्वारा लापरवाही बरतने वाले चिकित्सक पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। यदि समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया, तो क्षेत्र



की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहना पड़ेगा। यदि वर्तमान में देखा जाए तो सिविल अस्पताल में पदस्थ कुछ

चिकित्सक मरीजों के उपचार की बजाय खुद की कमाई पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कई बार तो ऐसी बातें भी छनकर बाहर आई हैं कि कुछ कर्मचारियों द्वारा मरीजों से पैसे तक ले लिए जाते हैं और कई बार तो लिए गए पैसे भी वापस करने पड़े हैं। अस्पताल में डॉक्टरों की समयानुसार नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होनी चाहिए और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्टर साहब एक नजर इधर भी जिसकी वजह से शायद

यहां की व्यवस्था सुधर जाए। सिविल अस्पताल पेटलावद की यदि व्यवस्था सुधर जाए तो नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में हर बीमारी का इलाज करने वाले बंगाली डॉक्टरों की दुकानें भी बंद हो सकती हैं। कुछ लापरवाह डॉक्टरों की वजह से ही क्षेत्र में बंगाली डॉक्टर चांदी काट रहे हैं। सूत्रों की माने तो कुछ कर्मचारी तो यहां पहुंचने वाले लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जिसकी वजह से उन्हें प्रायवेट अस्पताल की तरफ रुख करना पड़ता है और कुछ कर्मचारियों की व्यवहार से तो ऐसा लगता है कि इन कर्मचारियों और प्रायवेट अस्पताल के डॉक्टरों के बिक गठजोड़ है। जो भी हो आमजन की ओर से जिम्मेदार अधिकारियों से मांग है कि आमजन के फायदे के लिए अस्पताल की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए।

जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत नवांकुर/मेंटर्स की समीक्षा बैठक आयोजित

संजय जैन सह संपादक

झाबुआ। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद, विकासखंड पेटलावद द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नवांकुर एवं मेंटर्स की समीक्षा बैठक विकासखंड कार्यालय में आयोजित की गई।

बैठक में जिला समन्वयक प्रेमसिंह चौहान द्वारा अभियान अंतर्गत नवांकुर एवं मेंटर्स द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत

समीक्षा की गई। साथ ही आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा करते हुए सेक्टर स्तर पर सामूहिक श्रमदान आयोजित करने की योजना तैयार की गई।

बैठक के दौरान समितियों के माध्यम से किए गए विभिन्न कार्यों जागरूकता रैली, जल चौपाल, दीवार लेखन, सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक श्रमदान तथा तालाब एवं नदी गहरीकरण से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए।

विकासखंड समन्वयक प्रवीण कुमार द्वारा विकासखंड में संचालित गतिविधियों



की जानकारी साझा की गई। इस अवसर पर नवांकुर संस्थाओं के प्रतिनिधि अर्नसिंह, अरड दिनेश परमार, प्रवीण यादव, हरिराम, भूपेंद्र सिंह, मेंटर्स लालचंद, देवचंद एवं सीएम सोशल इंटरन नितेश मेड़ा उपस्थित रहे।

27 अप्रैल को कृषि आदान व्यापारियों का एक दिन का देशव्यापी बंद

जमना प्रसाद चौबे

दमोह। देश के खाद, बीज एवं कीटनाशक व्यापारियों के राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर 27 अप्रैल 2026 को देश के समस्त खाद, बीज एवं कीटनाशक व्यापारी एक दिन के सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनमोहन कलन्त्री ने बताया कि खाद, बीज एवं कीटनाशक व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को लगातार राज्य एवं केंद्र सरकारों के सामने उठाए जाने के बाद भी निराकरण नहीं किए जाने के विरोध में महाराष्ट्र राज्य संगठन (माफड़ा) द्वारा 27 अप्रैल से अनिश्चितकालीन बंद का आवाहन किया गया है।

उसके समर्थन में देश के सभी राज्यों में खाद, बीज एवं कीटनाशक व्यापारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। उपरोक्त जानकारी देते हुए संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री संजय रघुवंशी ने बताया कि जिन मुद्दों को लेकर यह सांकेतिक हड़ताल की जा रही है उनमें उर्वरकों में डीलर मार्जिन को डेढ़ प्रतिशत से बढ़कर कम से कम 8 प्रतिशत किया जाना। भारत सरकार की नीति के अनुसार रिटेलर के गोदाम तक उर्वरकों की पहुंच उपलब्ध करवाना।

खाद बीज एवं कीटनाशक के सैंपल फेल होने पर निर्माता एवं उत्पादक कंपनियों पर कार्रवाई करना एवं व्यापारी को गवाह के रूप में प्रस्तुत करना। साथी पोर्टल के माध्यम से लागू के लिए जाने वाली बीज विक्रय योजना को उत्पादक कंपनियों तक ही सीमित रखना। निर्माता कंपनियों द्वारा

उर्वरकों के साथ की जा रही अन्य उत्पादों की जबरन टैगिंग को पूर्ण रूप से बंद



करना। देश में लागू की जा रही ई टोकन प्रणाली को स्थगित करना। आदि अनेक मुद्दों पर लगातार संवाद किए जाने के बाद भी समस्याओं का निराकरण नहीं होने के कारण उपरोक्त एकदिवसीय हड़ताल अभी सांकेतिक रूप से की जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम प्रत्येक तहसील, विकासखंड एवं जिला स्तर पर बंद करके जुलूस निकाल कर ज्ञापन दिए जाएंगे और यदि एक माह में इन समस्याओं पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो आगामी खरीफ सीजन के पूर्व अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा भी की जा सकती है। प्रदेश अध्यक्ष श्री मानसिंह राजपूत ने प्रदेश के समस्त खाद, बीज एवं कीटनाशक व्यापारियों से अपील की है कि वह 27 अप्रैल को 1 दिन के बंद के आह्वान में पूर्ण रूप से सहयोग करें एवं अपने कृषि आदान व्यापार को भविष्य में जिंदा रखने का जो प्रयास और इंडिया संगठन द्वारा किए जा रहे हैं उसमें सहयोग प्रदान करें।

सीएम डॉ. मोहन यादव के प्रयासों का दिखा असर, 100 लाख मीट्रिक टन हुआ गेहूं खरीदी कोटा

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसान कल्याण के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं, इसका अंदाजा इस फैसले से लगाया जा सकता है। उनके अनुरोध पर केंद्र सरकार ने प्रदेश का गेहूं खरीदी कोटा बढ़ा दिया है।

भारत सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए 78 लाख मीट्रिक टन का कोटा निर्धारित किया था, जिसे अब बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है।

यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान हितैषी भावना को दर्शाता है।

केंद्र सरकार के गेहूं खरीदी का कोटा बढ़ाने के बाद सीएम डॉ. यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, मध्यप्रदेश के किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय। प्रदेश में इस वर्ष गेहूं उत्पादन बढ़ा है, इसलिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया था। मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार ने तत्परता दिखाते हुए कोटा 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। गेहूं खरीदी चरणबद्ध तरीके से पहले छोटे किसानों, फिर मध्यम और बाद में बड़े किसानों से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का प्रदेश के अन्नदाताओं की ओर से हार्दिक



आभार व्यक्त करता हूं। यह निर्णय किसानों के परिश्रम का सम्मान है, उन्हें उचित मूल्य दिलाने की दिशा में सशक्त कदम है।

किसान कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता गौरतलब है कि, प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। वे किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार फसल बीमा, सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, और किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने जैसी कई पहलें कर रही है। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को त्वरित राहत प्रदान करने के लिए भी सरकार सक्रिय रूप से काम कर रही है।

दिख रहा सकारात्मक बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नीतियों का स्पष्ट उद्देश्य

है किसानों की आय बढ़ाना, खेती को लाभकारी बनाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

को मजबूत करना। केंद्र और राज्य के समन्वय से किसानों को योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में किसान कल्याण की दिशा में किए जा रहे प्रयास न केवल

वर्तमान को सुदृढ़ कर रहे हैं, बल्कि भविष्य के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं।

पवई के छिरहा बांध में डूबा 12 वर्षीय मासूम

समीम मंसूरी

पवई। पन्ना जिले के पवई से दिल दहला देने वाली खबर। छिरहा बांध में नहाते समय 12 साल के मासूम शिवम चौधरी की



डूबने से मौत। एसडीईआरएफ ने 20 घंटे की मशकत के बाद आज शव बरामद किया। पूरे गांव में मातम का माहौल है। पवई थाना क्षेत्र के ग्राम करही में बुधवार दोपहर बृजेश चौधरी का 12 वर्षीय पुत्र शिवम अपने दोस्तों के साथ छिरहा बांध में नहाने गया।

अचानक गहरे पानी में फंस गया। दोस्तों के प्रयास नाकाम। सूचना पर एसडीईआरएफ पन्ना की टीम उपनिरीक्षक सत्यपाल जैन के नेतृत्व में पहुंची। 20 घंटे के रेस्क्यू के बाद गुरुवार को शव बरामद। पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा।

हमारी टीम को बुधवार शाम को सूचना मिली। रातभर सर्च चला, लेकिन सफलता न मिली। आज सुबह दोबारा ऑपरेशन शुरू किया। डाइवर्स ने कड़ी मशकत कर शव बाहर निकाला। यह बहुत दुखद है, हम बच्चों को पानी के किनारे सावधानी बरतने की अपील करते हैं। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

-सत्यपाल जैन, उपनिरीक्षक, एसडीईआरएफ

कृषि भू-अर्जन पर 4 गुना मुआवजे की घोषणा का स्वागत, भाजपा किसान मोर्चा ने जताया आभार

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा कृषि भूमि अधिग्रहण पर किसानों को बाजार दर से चार गुना मुआवजा देने की घोषणा के बाद प्रदेशभर में इसका स्वागत किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आभार कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा और विधायक भगवानदास सबनानी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया। नेताओं ने इस निर्णय को किसानों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और किसानों को उनकी जमीन का उचित मूल्य मिल सकेगा। भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से किसान संगठनों द्वारा उचित मुआवजे की मांग उठाई जा रही थी। कई बार यह देखा गया कि अधिग्रहण के दौरान किसानों को बाजार मूल्य से कम राशि मिलती थी, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। ऐसे में सरकार का यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया



और इसे-किसान हितैषी सरकार- का उदाहरण बताया। वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार लगातार किसानों के कल्याण के लिए योजनाएं लागू कर रही है, जिनमें फसल समर्थन मूल्य, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत पैकेज शामिल हैं।

कार्यक्रम के अंत में किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे सरकार की किसान कल्याणकारी नीतियों को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, ताकि अधिक से अधिक किसान इनका लाभ उठा सकें।

छिरर्हा में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ, कलश यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

समीम मंसूरी पवई (पन्ना)। ग्राम छिरर्हा, तहसील पवई, जिला पन्ना (मध्यप्रदेश) में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं चारों धाम हवन का भव्य आयोजन 23 अप्रैल से 01 मई 2026 तक किया जा रहा है। एवं श्री श्री 108 श्री नर्वदेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा 29,4,2026 को की जानी है।

आयोजन की शुरुआत विशाल कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं एवं पुरुषों ने भाग लेकर पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया।

कलश यात्रा ग्राम के विभिन्न मार्गों से होती हुई कार्यक्रम स्थल श्री कृष्ण कुंज, छिरर्हा पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। आयोजन स्थल पर आकर्षक पंडाल सजाया गया है, जहां प्रतिदिन भगवान की कथा, भजन-कीर्तन और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जा रहे हैं।

इस धार्मिक आयोजन में विद्वान कथावाचकों द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित होकर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान चारों धाम हवन एवं प्राण प्रतिष्ठा जैसे



महत्वपूर्ण अनुष्ठान भी संपन्न होंगे, जिससे पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा है।

यह आयोजन परमपूज्य गुरुदेव पंडित श्री सुरेंद्र कुमार शास्त्री जी के सानिध्य में एवं कथावाचक पंडित श्री केशव प्रसाद मिश्र जी (चित्रकूट धाम) द्वारा किया जा रहा है। आयोजन में प्रमुख रूप से वल सिंह, नत्थू सिंह परमार (ठेकेदार), श्रीमति

मानकुंवर, रविन्द्र सिंह, एडवोकेट रामायण सिंह परमार एवं दीपेंद्र सिंह परमार, शैलेन्द्र सिंह की विशेष भूमिका है।

ग्राम सहित आसपास के क्षेत्रों में इस भव्य धार्मिक आयोजन को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। आयोजकों ने समस्त श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण कर धर्म लाभ लेने की अपील की है।

जिले के स्वैच्छिक एवं सामाजिक संगठनों की जिला स्तरीय बैठक कलेक्टर कार्यालय में सम्पन्न

आशीष वाणी

आलीराजपुर। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा जिले के स्वैच्छिक एवं सामाजिक संगठनों की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन कलेक्टर सभाकक्ष कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं नोडल अधिकारी संघमित्रा गौतम उपस्थित रहीं।

बैठक में बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद को स्वैच्छिक संगठनों (एनजीओ) की नोडल एजेंसी बनाया गया है। परिषद के माध्यम से 'दृष्टि योजना' अंतर्गत 'पंख कार्यक्रम' प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत वन एवं पर्यावरण, जल संरक्षण, ऊर्जा, जैविक एवं प्राकृतिक कृषि, नशा मुक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक सशक्तिकरण, स्वदेशी, सामाजिक समरसता तथा नागरिक कर्तव्यों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत उत्कृष्ट स्वैच्छिक संगठनों के कार्यों एवं उनकी कार्यप्रणाली को विस्तार प्रदान किया जाना है। इसी उद्देश्य से आगामी अप्रैल-मई 2026 में राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके लिए जिले में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जिला स्तरीय डायरेक्टरी तैयार की जा रही है। बैठक में जिला समन्वयक द्वारा जन अभियान परिषद की गतिविधियों एवं परिषद से जुड़े स्वैच्छिक संगठनों की

जानकारी की गई।

बैठक में कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने कहा कि जिले के स्वैच्छिक संगठन समाज विकास एवं जनजागरूकता में



महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने सभी संगठनों से जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाली गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने बावड़ियों की साफ-सफाई, जल स्रोतों के गहरीकरण, जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रमों एवं श्रमदान गतिविधियों में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। साथ ही आगामी महिला साक्षरता अभियान में भी स्वैच्छिक संगठनों से सक्रिय सहयोग प्रदान करने की अपील की।

बैठक में नोडल अधिकारी एवं जिला

पंचायत सीईओ संघमित्रा गौतम ने पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जिले में परिषद एवं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित सेवा कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने

योजनाबद्ध एवं परिणाममूलक कार्य करने पर जोर देते हुए कहा कि प्रशासन और स्वैच्छिक संगठनों के समन्वय से समाजहित में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। बैठक के दौरान विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में किए जा रहे सामाजिक एवं जनहित कार्यों की जानकारी साझा की।

बैठक में कृषि, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग के प्रमुख अधिकारी सहित जिले के विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

युवा संगम मेले में 33 युवाओं को मिला रोजगार, 57 का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

आशीष वाणी

आलीराजपुर। जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेजावाडा, चन्द्रशेखर आजाद नगर में आज 23 एक दिवसीय युवा संगम मेले का सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को एक ही मंच पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना रहा। इस जिला स्तरीय आयोजन में निजी क्षेत्र की 4 कंपनियों ने भाग लिया। मेले में कुल 57 युवाओं ने भागीदारी की, जिनमें से 33 युवाओं का प्रारंभिक चयन कर उन्हें ऑफर लेटर प्रदान किए गए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग श्री भुपेन्द्र मण्डलोई एवं उनकी टीम द्वारा सभी 57 प्रतिभागियों का स्वास्थ्य

परीक्षण भी किया गया।

कार्यक्रम के दौरान जिला व्यापार एवं



उद्योग विभाग के प्रबंधक श्री रोहित भिण्डे ने युवाओं को स्वरोजगार से संबंधित विभिन्न शासकीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही जिले में विकसित औद्योगिक क्षेत्रों एवं वहां उपलब्ध भूखंडों के आवंटन संबंधी जानकारी देकर युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया।

कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोंगरगांव का रेडियोग्राफर किया गया निलंबित

राजनांदगांव। संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें रायपुर संभाग रायपुर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजनांदगांव से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोंगरगांव में पदस्थ रेडियोग्राफर भोज कुमार साहू को पदीय कर्तव्यों में घोर लापरवाही एवं गंभीर अनुशासनहीनता बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोंगरगांव के रेडियोग्राफर भोज कुमार साहू

द्वारा शासकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने, पदीय दायित्वों का निर्वाहन नहीं करने, शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न करने, उच्च अधिकारियों से अनुचित वार्तालाप करने तथा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। भोज कुमार साहू का कृत्य गंभीर अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्यों के प्रति लापरवाही के श्रेणी में होने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों के शर्तों का उल्लंघन है।